चार कदमों से भारत प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बन सकता है आत्मनिर्भर

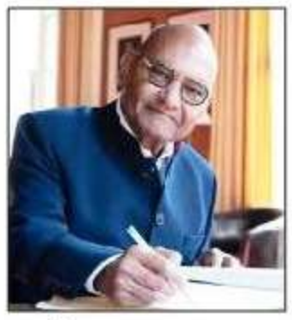

अनिल अग्रवाल

देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए देश को आत्मनिर्भर भारत का रास्ता ही अपनाना होगा, क्योंकि कोई भी देश आयातक बनकर विकसित नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात से भलीभांति वाकिफ हैं और उनका आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का आह्वान बिल्कुल सही समय पर है। अगर हम देश के आयात बिल पर नजर डालें, तो कच्चा तेल, सोना, तांबा और बॉक्साइट की हिस्सेदारी इसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा है। दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक्स सामान भी आयात में 15 प्रतिशत की बड़ी हिस्सेदारी रखता है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात को कम करने के लिए घरेलू उत्पादन पर काफी जोर दिया है और इसमें काफी सफलता भी मिली है। इसी तरह अब समय आ गया है कि आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के घरेलू उत्पादन को भी प्राथमिकता के तौर शामिल किया जाए। सौभाग्य से देश की धरती खनिजों से भरी पड़ी है, प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से भारत की भूगौलिक स्थिति ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बराबर है। लाखों साल पहले, ये सभी भौगोलिक क्षेत्र एक ही भूभाग का हिस्सा थे, और भारत समेत इन सभी में खनिजों और हाइड्रोकार्बन के बड़े बड़े भंडार हैं। अंतर केवल इतना है कि अन्य भौगोलिक क्षेत्रों यानि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका ने अपने खनिज भंडारों को खोजा और उनका खनन किया। लेकिन हम अभी इसमें पिछड़े हुए हैं। हमारी धरती में बहुमूल्य खनिज भंडारों को देखते हुए, कोई कारण नहीं है कि भारत को कोई प्राकृतिक संसाधन आयात करना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत तीन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों – कच्चा तेल, सोना और तांबा के मामले में आयात पर निर्भर है, जिसकी वजह से देश का

व्यापार घाटा पिछले वित्त वर्ष में 238 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। यह तीनों प्रमुख प्राकृतिक संसाधन कुल संसाधनों के आयात का 60 प्रतिशत हिस्सा हैं। हम अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 90 प्रतिशत, तांबे की आवश्यकता का 95 प्रतिशत और सोने की आवश्यकता का 99 प्रतिशत से अधिक आयात करते हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में कोयला और बॉक्साइट का भी आयात करते हैं, जबकि हमारे यहां कोयला और बॉक्साइट बड़ी मात्रा में हैं। लेकिन यह स्थिति केवल चार नीतिगत उपायों से पूरी तरह से बदल सकती हैं, पहला खनन का नया तरीका, पर्यावरण एवं अन्य मंजूरियों का सेल्फ सर्टिफिकेशन, मौजूदा खनिज परिसंपत्तियों का पुनरुद्धार और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच समान अवसर। सबसे पहले, खनन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। दुनियाभर में खनन का काम छोटी जूनियर खनन कंपनियां करती हैं, जो बड़ी कंपनियों की तुलना में स्टार्टअप की तरह अधिक काम करती हैं। वे खनन के हाई रिस्क को उठाती हैं। जिसमें 10 में से 9 बार खनिज की खोज में मायूसी हाथ लगती है। लेकिन दुनियाभर में इस 10 में से एक खोज से यह कंपनियां पैसा कमाकर अपने खनिज खोज के काम को आगे बढ़ाती रहती हैं। भारत में खनिजों की खोज की वर्तमान नीति व्यवस्था में खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की जाती है। लेकिन यह प्रणाली काम नहीं करती। आज भी भारत में मोटे तौर पर, सरकार ही आधारभूत खनन का काम करती है और दो सार्वजनिक क्षेत्र की दोनों प्रमुख खनन कंपनियों के पास पूरे देश में बेहतर तरीके से खनन करने के लिए न तो बैंडविड्थ है और न ही संसाधन। आइए हम अपने युवा उद्यमियों पर इस खनन के लिए भरोसा करें। बस सरकार को चाहिए कि खनिज की खोज से फीस हटा दे। खनिज की खोज होने पर सरकार, किसी भी स्थिति में, रॉयल्टी और टैक्स तो वसूलेगी ही, जिससे उसकी कमाई होगी। दूसरा, प्रक्रियाओं में तेजी लानी होगी। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में खनिज की खोज से खनन तक पहुँचने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन भारत में, दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा समय लगता है क्योंकि इसमें पर्यावरण से लेकर दूसरी कई मंजूरियाँ शामिल होती हैं और उन्हें देने में लंबा वक्त लगता है। इस तरह की जटिल प्रणाली के बजाय, हमें सेल्फ सर्टिफिकेश की ओर बढ़ना चाहिए। सरकार मानदंडों और मानकों की एक नियम पुस्तिका बना सकती है जिनका पालन करना अनिवार्य है। उद्यमियों को सेल्फ सर्टिफिकेश करना होगा। बाद में, एक ऑडिट प्रक्रिया के माध्यम से, सरकार किसी भी चूक के लिए कंपनियों को जवाबदेह ठहरा सकती है। जैसा की सरकार आयकर जैसे कुछ क्षेत्रों में कर रही है। आयकर भी लोग खुद जमा कराते हैं और बाद में सरकार उसकी जांच करती है। सरकार इस प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रही है। तीसरा, उन मौजूदा परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित करें और उन्हें नई ऊर्जा प्रदान करें जो या तो निष्क्रिय पड़ी हैं या जिनका उत्पादन लगातार गिर रहा है। तेल, तांबा और सोने की मौजूदा खानों का एक बड़ा हिस्सा सरकार के पास है। इनमें से कई जैसे कोलार गोल्ड फील्ड्स निष्क्रिय पड़ी हुई हैं।

जबकि तांबे में हिंदुस्तान कॉपर या हट्टी गोल्ड माइन कुछ दशकों से कम उत्पादन कर रही हैं। अन्य तेल जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश की प्रतीक्षा हो रही हैं। इन्हें निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोला जा सकता है। और निजी क्षेत्र की भागीदारी से इनमें नए निवेश और नवीनतम तकनीक के इस्तेमाल से तुरंत परिणाम मिलेंगे, जबकि खनिज की नई खोजों को अगर सबसे तेज मंजूरी भी मिल जाए तो भी परिणाम मिलने में भी समय लगता है। चौथा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा के लेवल प्लेइंग फिल्ड बनाना। प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में अभी भी बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का दबदबा है, जिन्हें अक्सर वित्तीय सहायता या नोमिनेशन के जरिए से ब्लॉक आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है। इससे निजी क्षेत्र को लेवल प्लेइंग फिल्ड नहीं मिलती है। उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, विशेष रूप से युवा उद्यमियों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बड़ी बात यह है, देश को प्राकृतिक संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के इन चारों उपायों के लिए किसी भी तरह के सरकारी बजट की जरूरत नहीं है। बल्कि यह तो सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी ही करेंगे। साथ ही इन उपायों से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और लाखों नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, सबसे बढ़कर आयात बिल की वजह से जो नुकसान देश को हो रहा है, उससे बचकर हम देश को 2047 तक विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे।

लेखक : वेदांता समूह के अध्यक्ष हैं।